श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : यह गरीब किसानों का मसला है ।

श्री छोटू भाई पटेल : मैडम, डिप्टी चेयरमैन, फार्मर्ज़ की जो मांगें हैं . . . . **(व्यवधान)**

उपसभापति : प्लीज़, मंत्री जी, आप मालूमात कर लीजिए स्टेट गवर्नमेंट से दोबारा जो यह मेंबर . . . . **(व्यवधान)** छोटू भाई, जस्ट ए मिनट । आप स्टेट गवर्नमेंट से इसका पूरी तरह से पता लगा लीजिए । जब आपको मालूम हो जाएगा कि जो यह मेंबर्ज़ कह रहे हैं वह ठीक है . . . . **(व्यवधान)** लीजिए और मेंबर्ज़ को लिख कर बता दीजिए कि इस सिलसिले में सही स्थिति क्या है ।

श्री अरविंद नेताम : ठीक है, मैडम ।

श्री छोटू भाई पटेल : मैडम, डिप्टी चेयरपर्सन जो इंशोरेंस की गुजरात के फार्मर्ज़ की जो पुरानी मांगें हैं 1990 से वह जल्दी निपटाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है ? जो 40 करोड़ की डिमांड है जिसको अस्वीकार किया गया है तो क्रॉप इंशोरेंस कमेटी के तहत दोबारा चैक करवा कर यह फार्मर्स को धनराशि देने के लिए सरकार क्या सोच रही है और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में जोड़िया, कलावार दोनों तालुका ब्लाक्स हैं, वहां के फार्मर्स की डिमांड को काउंट नहीं किया गया है तो उसके बारे में सरकार इसको स्वीकार करने के लिए क्या सोच रही है ?

श्री अरविंद नेताम : महोदया, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न में कहा कि जो 47 करोड़ हैं, वह राज्य सरकार शेयर दे दे तो हम तुरन्त इसकी पेमेंट कर देंगे । दूसरा जोड़िया ब्लाक के बारे में जो कहा गया है उसमें कुछ डिसक्रीपेंसी है, जैसा कि मैडम, आपने कहा है, मैं फिर से इसे एग्ज़ामिन करवा लूंगा और उसके बाद उसे मैं सदन के सामने रखूंगा ।

SHRI P. UPENDRA: Madam, the very purpose of the Crop Insurance Scheme is being lost because of the guidelines according to which the block is being taken as a unit. It is just like insisting that for life insurance, people in the whole area should die. Will he consider revising the scheme according to which a Gram Panchayat or a Village will be made a unit ?

श्री अरविंद नेताम : महोदया, जैसे कि अभी नई पायलट स्कीम विचाराधीन है कैबिनेट के सामने और इसमें नई स्कीम के बारे में मुख्य मंत्री सम्मेलन में यह चर्चा हो गई है और उसमें यह जो आप माननीय सदस्य कह रहे हैं वह एक कंडीशन है, इसलिए फिर से नया स्वरूप दिया जा रहा है और कैबिनेट से पास हो जाएगा तो फिर आपके सामने रखा जाएगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Off take of fertilisers during khariff season

*164. SHRI GAYA SINGH .
SHRI CHATURANAN MISHRA:
Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the off take of fertiliser for the khariff season this year has been poor; and

(b) if so, the details thereof and also the reasons therefor ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR) : (a) and (b) As on 15-7-1993, the off take of Urea registered an increase of 27% compared to the same period last year while that of DAP and MOP registered a decline of 56% and 44% respectively. Decline in the sale of Phosphatic and Potassic fertilisers has been mainly due to the increase in prices consequent on their decontrol in August, 1992.

Increase in the percentage of illiterates

*165. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:
SHRI GHUFRAN AZAM:
Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "300 m Indians still illiterate : UNICEF" which appeared in the Times of India dated the 23rd June, 1993;

(b) if so, whether it is a fact that the percentage of illiterates in some states is increasing; and

(c) if so, what steps Government propose to take in this regard ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) However, in order to eradicate illiteracy, some of the steps taken in recent years include :

(i) The National Literacy Mission was launched in May, 1988 with the objective of imparting functional literacy to 80.00 million adult illiterates in the 15-35 age group by 1995.

(ii) The Total Literacy Campaigns (TLC) constitute the dominant strategy under the Mission. These campaigns are area specific, time bound, result oriented, volunteer based and cost effective.

(iii) At present 213 districts have been covered by such Total Literacy Campaigns and 75 districts by Post Literacy Campaigns.

दिल्ली में टैन्टों में चलने वाले स्कूल

*166. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल :**
श्री विश्वम्भर नाथ पांडे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अभी भी बड़ी संख्या में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल ऐसे हैं जिन्हें टैन्टों में चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या ऐसे स्कूलों के लिए स्थायी भवन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के बारे में सरकार की कोई योजना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली में, अधिकांशत: स्कूल दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जाते हैं । इन अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम के नियंत्रणाधीन टैन्ट में चलने वाले स्कूलों की संख्या क्रमश: 109 तथा 90 है ।

टैन्टों का उपयोग करने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—स्कूल स्थलों की उपलब्धता न होना, विभिन्न बस्तियों की बढ़ती हुए मांग के कारण स्कूल खोलना/उनका स्तर ऊंचा करना/दो शाखाओं में विभाजित करना, विवादित स्थल इत्यादि ।

दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम प्रत्येक स्कूल को समुचित भवन उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं । जिन स्कूलों के पास अपने निजी भवन नहीं हैं उन स्कूलों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध होने पर तथा उपलब्ध निधियों की सीमा के भीतर स्थायी भवन के निर्माण का काम हाथ में लिया जाता है ।

*167. [*Transferred to 16th August, 1993*]

Establishment of an affiliating University in Delhi

168. SHRI SHANTI TYAGI : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have approved the establishment of an affiliating University in Delhi as part of the National Capital Region Plan envisaged to decongest Delhi;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) by when the affiliating University is likely to commence functioning ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) to (c) The University Grants Commission (UGC) has constituted a Committee under the Chairmanship of Prof. Bipin Chandra, Member, UGC to examine the feasibility and desirability of either setting up an affiliating University in Delhi or of affiliating Colleges in the region with Deemed Universities, including School of Planning and Architecture, New Delhi. The terms and reference of Committee are as under :

(i) To examine the feasibility and desirability of both suggestions and to advise about the legal and management implications of the suggested solutions.

(ii) To recommend and suggest the operational mechanism, if the idea is found recommendable.

Performance of Kendriya Vidyalaya Students

*169. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of students who appeared from Kendriya Vidyalayas for Central Board of Secondary Examination during 1991-92 and 1993 separately for Arts, Commerce and Science group;

(b) the number of students who passed with more than seventy per cent of marks in each discipline;

(c) what had been the average performance of Delhi students as a whole; and

(d) the steps taken to improve the teaching standard in the Kendriya Vidyalaya specially in Delhi ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) to (d) Upto class X, there are no subject-wise streams and all the subjects taught are compulsory. There are subject-wise streams at plus 2 stage. However, Central Board of Secondary Education, to which all the Kendriya Vidyalayas are affiliated, does not issue marks and results according to subject-wise stream.